बाढ़ से डूबी फसलें, शिवराज ने लिया जायजा

अमृतसर, कपूरथला, गुरदासपुर के खेत जलमग्न

बाढ़ से तबाह हुए खेत, सरकार करेगी मदद

अमृतसर, 4 सितंबर लगातार भारी बारिश और नदी-नालों में उफान के चलते पंजाब के कई जिले जलमग्न हो गए हैं. सबसे ज्यादा असर अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर में देखा जा रहा है.

खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं. इस गंभीर स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को पंजाब पहुंचे. चौहान ने सबसे पहले अमृतसर जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से बातचीत की. किसानों ने बताया कि उनकी सालभर की मेहनत पानी में बह गई. खेतों में गेहूं, धान और मक्के की फसलें डूब चुकी हैं. चौहान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर संभव सहायता के लिए तैयार है. बाद में उन्होंने कपूरथला और गुरदासपुर जिलों का भी दौरा किया. इन इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर है. गुरदासपुर में 324 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और 40,169 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है. इसी तरह कपूरथला में 123 गांव प्रभावित हैं और लगभग 3,000 हेक्टेयर भूमि पर पानी भर गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं. किसानों और बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव मदद दी जाएगी. राज्य सरकार के मुताबिक, अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है और 1,655 गांव बाढ़ की चपेट में हैं.

> शिवराज ने कहा कि मेरे किसान भाई-बहनों का दु:ख मेरा अपना है. केंद्र सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है. राहत और पुनर्वास के हर कदम को प्राथमिकता दी जाएगी. शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हालात की निगरानी कर रहे हैं और समय-समय पर अपडेट ले रहे हैं. जल्द ही केंद्र सरकार एक उच्च स्तरीय राहत पैकेज पर निर्णय लेगी. किसानों को बीमा और आर्थिक सहायता शीघ्र मिलेगी. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं.

कार्यकर्ता राहत कार्यों में जुटे : केजरीवाल

दिल्ली में यमुना में बाढ़ का खतरा मंडराया

नई दिल्ली 4 सितंबर. दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक ट्वीट के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है. दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. मैं आप के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि प्रशासन के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्यों में जुट जाएँ

और हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचाएँ. इस अपील के तुरंत बाद पार्टी के कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को भोजन, पानी, दवाइयां और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया. आप यूथ कोऑर्डिनेटर

नवनीत सिंह नीतू के निधन पर जताया शोक: आम आदमी पार्टी के यूथ क्लब हलका मानसा के कोऑर्डिनेटर नवनीत सिंह नीतू का एक दुखद सड़क हादसे में निधन हो गया. इस खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर है. नवनीत सिंह पिछले कई दिनों से पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए थे. घटना की जानकारी मिलते ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स के माध्यम से संवेदनाएं प्रकट की.

> केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा- आम आदमी पार्टी यूथ क्लब, हलका मानसा के कोऑर्डिनेटर नवनीत सिंह नीतू जी के सड़क हादसे में निधन की खबर बेहद दुखद है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार सेवा करने वाले नवनीत जी हर कार्यकर्ता के लिए मिसाल थे. इस कठिन समय में हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.

नीतीश ने 27 योजनाओं का किया शिलान्यास

सारण में 1203.81 करोड़ रुपये लागत की होंगे कार्य

पटना, 4 सितंबर (वार्ता). बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को सारण जिले में 1203.81 करोड़ रुपये लागत की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया.

कुमार ने छपरा के रतनपुर बिन टोलिया स्थित कार्यक्रम स्थल से सारण जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित 1203.81 करोड़ रुपये लागत की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया. इसके अंतर्गत 545 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से के.बी. ग्रिड उपकेंद्र, छपरा एवं 132 के.बी. के संचरण लाइन का निर्माण कार्य, 60 करोड़ एक लाख रुपये लागत की एचटीएलएस द्वारा रिकन्डक्टरिंग का कार्य, 93 करोड़ 62 लाख रुपये लागत की एकमा - मशरख पथ का चौड़ीकरण कार्य एवं 41 करोड़ 66 लाख रुपये लागत की एकमा से डुमाइगढ़ तक पथ का चौड़ीकरण कार्य शामिल है.

> सीएम ने विकासात्मक योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने से पहले छपरा के जगदम कॉलेज से खैरा बिन टोलिया तक किये जा रहे सड़क के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया. इस सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने से छपरा में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा. बिन टोलिया के पास बन रहे बस स्टैंड से रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी. मुख्यमंत्री ने पेंशनधारी लाभुकों, जीविका दीदियों के साथ संवाद किया.

नागपुर में सौर इकाई में विस्फोट में एक की मौत

नागपुर, 4 सितंबर (वार्ता). नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, बाजारगांव स्थित सौर संयंत्र में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच कर्मचारी घायल हो गए. जिनमें से तीन की हालत गंभीर है. कंपनी की पीपी-15 इकाई में रात लगभग 12.34 बजे विस्फोट हुआ, जिसमें 25 वर्षीय सुपरवाइजर मयूर गणवीर की मौत हो गई. कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में पांच कर्मचारी झुलस गए. उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.

यूक्रेन शांति में भारत की भूमिका अहम : ईयू

नई दिल्ली/ब्रसेल्स 4 सितंबर. यूक्रेन युद्ध के चलते पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की भूमिका को अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुले तौर पर सराहा जा रहा है.

इसी क्रम में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुरुवार को टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई. इस दौरान उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर विचार-विमर्श किया और वैश्विक शांति की दिशा में भारत की भूमिका को निर्णायक बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भारत की ओर से शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की और इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी पक्षों को संवाद के जरिए समाधान निकालने की जरूरत है. बातचीत में यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी प्रगति की बात कही गई और वर्ष के अंत तक बातचीत पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई. वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सार्थक बातचीत हुई. हम यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के सहयोग का स्वागत करते हैं. भारत इस संघर्ष को समाप्त करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है.

> उन्होंने आगे कहा कि यह युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और गहरा करना चाहता है। इसके तहत 2026 में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर सहमति बनाने की योजना है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब रूस-यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक स्थायी समाधान की तलाश में है। भारत, जो अब तक दोनों पक्षों से संवाद में संतुलन बनाए रखे हुए है, वैश्विक मंच पर शांति के लिए एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में उभरता दिख रहा है।

कोर्ट में याचिका स्थानांतण करने का केंद्र का अनुरोध

नई दिल्ली, 4 सितंबर (वार्ता). केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के प्रचार और विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की गुहार लगायी है. शीर्ष अदालत में दायर याचिका में संबंधित याचिकाओं को 3 उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है ताकि परस्पर विरोधी फैसलों से बचा जा सके. याचिकायें कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में लंबित हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने रूसी समकक्ष को दी परोक्ष धमकी

वाशिंगटन, 4 सितंबर(वार्ता). अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संबंध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए गए अपने संदेश के बारे में पूछे जाने पर चेतावनी जारी की.

ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस से कहा, राष्ट्रपति पुतिन के लिए मेरा कोई संदेश नहीं है. वह जानते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, और वह किसी न किसी तरह से कोई न कोई फैसला लेंगे. उनका जो भी फैसला होगा, हम या तो उससे खुश होंगे या नाखुश, और अगर हम उससे नाखुश हैं, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, राष्ट्रपति ने परोक्ष धमकी देते हुए कहा. रूस के खिलाफ प्रशासन की अब तक की कार्रवाइयों या उनकी कमी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गए. ट्रंप ने कहा, आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्या आप कहेंगे कि चीन के अलावा सबसे बड़े खरीदार भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाना लगभग बराबर है.

अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद अब कोर्ट में

वाशिंगटन, 4 सितंबर. भारत पर लगाए गए भारी अमेरिकी टैरिफ को लेकर अब मामला अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी शुल्क को अमेरिकी अपील अदालत ने पिछले हफ्ते गैर-कानूनी करार दिया था, जिसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने अब सुप्रीम कोर्ट में 251 पन्नों की विस्तृत अपील दाखिल की है. इस अपील में कहा गया है कि यह टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक शांति के लिए बेहद जरूरी हैं. ट्रंप का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजी वैश्विक आपात स्थिति से निपटने और अमेरिका की विदेश नीति को मजबूती देने के लिए यह कदम उठाया गया.

'अगर बिना दांत के बाघ है तो इसका उद्देश्य क्या है?' : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 4 सितंबर(वार्ता). उच्चतम न्यायालय ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए समान संहिता (यूसीपीएमपी) 2024 के संबंध में गुरुवार को सवाल किया कि अगर यह संहिता एक बिना दांत का बाघ है तो इसका उद्देश्य क्या है?

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वास्तविक कठिनाई मानदंडों के कार्यान्वयन में है. पीठ ने दवाओं के प्रचार के किसी भी अनैतिक तरीके पर अंकुश लगाने के मद्देनजर दवा कंपनियों की विपणन प्रथाओं के लिए एक समान संहिता की मांग वाली इस याचिका पर सुनवाई के दौरान और भी कई सवाल किये. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका में की गई गुहार का अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि एक वैधानिक व्यवस्था पहले से ही लागू है. इस पर पीठ ने कहा, मुश्किल यह है कि व्यवस्था तो मौजूद है.

जीएसटी से जेब पर अतिरिक्त बोझ : खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप

नई दिल्ली 4 सितंबर. कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने जिस वन नेशन, वन टैक्स का वादा किया था, उसे वन नेशन, 9 टैक्सेस में बदल दिया है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मौजूदा जीएसटी प्रणाली ने गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला है. ट्वीट में लिखा गया- दूध-दही, आटा-पेंसिल-किताबें, ऑक्सीजन, अनाज, इंश्योरेंस, अस्पताल इन सभी ज़रूरी चीज़ों पर मोदी सरकार ने जीएसटी थोपा है. इसीलिए हमने इसे 'गब्बर सिंह टैक्स' कहा था. मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि मौजूदा जीएसटी में 0%, 5%, 12%, 18%, और 28% जैसे मुख्य टैक्स स्लैब के अलावा 0.25%, 1.5%, 3% और 6% जैसी विशेष दरें भी हैं, जो सरलीकरण के वादे के खिलाफ हैं.

> मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बताया कि 28 फरवरी 2005 को यूपीए सरकार ने लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी और 2011 में प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए थे. लेकिन उस समय भाजपा और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया था. मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी हमला बोला है. आज यही भाजपा सरकार आम जनता से टैक्स वसूल कर जश्न मना रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो. जीएसटी का 64% हिस्सा गरीब और मिडिल क्लास से आता है, जबकि अरबपतियों से सिर्फ़ 3%. कांग्रेस ने सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर अगले 5 वर्षों तक मुआवज़ा देने की मांग की है ताकि जीएसटी दरों में संभावित कटौती से उनके राजस्व को नुकसान न हो.
>
> 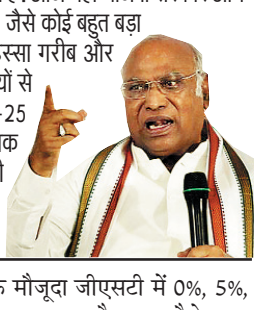

एक नजर में

चीन ने डोंगफेंग-5सी का किया प्रदर्शन

बीजिंग 4 सितंबर (वार्ता). चीन ने अपने 80वें विजय दिवस समारोह में परमाणु क्षमता से युक्त एक ऐसी मिसाइल का प्रदर्शन किया है जो पूरे विश्व में कहीं भी निशाना साध सकता है. रिपोर्टों के मुताबिक डोंगफेंग-5 नाम का यह मिसाइल अंतरमहाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल डोंगफेंग -5बी की अगली पीढ़ी का है. तरल ईंधन से चालित यह लंबी दूरी का रणनीतिक परमाणु मिसाइल है, जो परमाणु वारहेड को पूरे विश्व में कहीं भी ले जाने में सक्षम है. साथ ही चीन ने इस परेड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण हथियारों को भी प्रदर्शित किया. ड्रोन और इन जैसे अन्य हथियारों को मार गिराने वाले 99 ए टैंक, चांगजियान-20ए और चांगजियान-1000 जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, लंबी दूरी से विमानवाहक पोतों पर हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक वाईजे-21, पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम) जेएल-3 आदि हथियार परेड में शामिल थे.

अमेरिका का वेनेजुएला की नाव पर हमला, 11 मृत

वॉशिंगटन डीसी, 4 सितंबर. अमेरिकी सेना ने मंगलवार को कैरिबियन सागर में एक वेनेजुएला की नाव पर सीधा हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इस कार्रवाई की पुष्टि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की है. उनका कहना है कि यह आदेश खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया था क्योंकि नाव में भारी मात्रा में 'कोकीन या फेंटेनाइल' जैसे घातक ड्रग्स लदे होने की आशंका थी. विदेश मंत्री रुबियो ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी एजेंसियों के पास खुफिया जानकारी थी कि यह नाव ड्रग्स लेकर त्रिनिदाद या अमेरिका की ओर जा रही थी. हम इसे रोक भी सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प का मानना था कि केवल ड्रग्स पकड़ने से कार्टेल नहीं रुकेंगे उन्हें खत्म करना होगा, रुबियो ने कहा. रुबियो के अनुसार नाव को चेतावनी दिए बिना ही हमला किया गया क्योंकि इसे सीधा खतरा माना गया. इस घटना का एक वीडियो भी ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें एक स्पीडबोट तेजी से दौड़ती दिख रही है और फिर उसमें विस्फोट हो जाता है. हालांकि वीडियो में स्पष्ट नहीं है कि नाव में लोग मौजूद थे या नहीं, और ड्रग्स के पैकेटों की भी पुष्टि नहीं हो पाई है. पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रेस को बताया कि मारे गए लोग ट्रेन डे अरागुआ गिरोह से जुड़े थे जिसे अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है. ट्रम्प ने दावा किया, हमारे पास उनकी बातचीत के टेप हैं और यह नाव हजारों लोगों को मार सकने वाले ड्रग्स ला रही थी. अब वे दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करेंगे. इस हमले को लेकर अमेरिकी प्रशासन में ही मतभेद सामने आ रहे हैं. रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने सवाल उठाया कि क्या इतनी छोटी नाव में सचमुच 11 लोग हो सकते थे?

कर्मचारियों को अब 10 घंटे काम करना होगा

महाराष्ट्र में श्रम कानूनों में हुआ बदलाव

मुंबई, 4 सितंबर (वार्ता). महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में श्रम कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के बाद अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजाना नौ घंटे की बजाय 10 घंटे काम करना होगा.

आयोजित महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर इन बदलावों को मंजूरी दी गई. श्रम कानूनों में हुए इस बदलाव के बाद अब वह कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों की श्रेणी में आ गया है. जिन्होंने पहले ही इसी तरह के सुधार लागू कर दिए हैं. फैक्ट्री अधिनियम 1948 में संशोधनों से कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें उद्योगों में दैनिक कार्य घंटे नौ से बढ़ाकर 12 घंटे करना शामिल है. अब लगातार छह घंटे काम करने के बाद विश्राम अवकाश अनिवार्य है, जो पहले पांच घंटे था राज्य में श्रम कानूनों में हुए इस संशोधन के बाद ओवरटाइम की सीमा को प्रति तिमाही 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है. जबकि साप्ताहिक कार्य घंटे 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं.

> राज्य में श्रम कानूनों में हुए बदलाव के बाद अब ओवरटाइम काम करने के लिए श्रमिकों की अनिवार्य लिखित सहमति आवश्यक होगी तथा किसी भी श्रमिक को उनकी सहमति के बिना ओवरटाइम कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों के लिए दैनिक कार्य समय नौ से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है. साथ ही ओवरटाइम की सीमा प्रति तिमाही 125 से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है. आपातकालीन ड्यूटी की अवधि बढ़ा दी गई है जो अब 12 घंटे की होगी.

आज का इतिहास

1666 इंग्लैंड के शहर लंदन में लगी भीषण आग में 13,200 घर क्षतिग्रस्त हो गये।

1836 मशहूर अमेरिकी राजनीतिज्ञ सैम ह्यूस्टन टेक्सास गणराज्य के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए।

1839 चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध की शुरुआत

1882 पहला अमेरिका श्रम दिवस परेड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया।

1885 अमेरिका के इंडियाना स्थित फोर्ट वेयन में पहली बार गैसोलीन पंप की स्थापना

1887 इंग्लैंड के थिएटर रॉयल एक्सेटर में आग लगने से 186 लोगों की मौत।

गवई ने मानव गरिमा को बताया संविधान की आत्मा

नई दिल्ली, 4 सितंबर. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि उच्चतम न्यायालय के शीर्ष पद तक पहुंचने का श्रेय भारतीय संविधान और डॉ. भीमराव अम्बेडकर को दिया है.

डॉ. एलएम सिंघवी स्मृति व्याख्यान के 11वें संस्करण में उन्होंने गरिमा, समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों पर गहन विचार रखते हुए कहा कि मानव गरिमा ही संविधान की आत्मा है. इस अवसर पर उन्होंने भारतीय न्यायपालिका द्वारा गरिमा की रक्षा में दिए गए ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख भी किया. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित 11वें डॉ. एलएम सिंघवी स्मृति व्याख्यान में भावुक और प्रेरणादायक भाषण देते हुए कहा कि उनका आज उच्चतम न्यायालय तक पहुँचना भारतीय संविधान और बाबासाहेब अम्बेडकर की दूरदर्शिता का परिणाम है.

भावनगर में 350 करोड़ की लागत से बनेंगे 40 रोड अंडर ब्रिज

भावनगर, 4 सितंबर. पश्चिम रेलवे में गुजरात के भावनगर मण्डल में लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत से 40 रोड अंडरब्रिज बनाये जायेंगे. मंडल रेल प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि यात्रियों की सुविधा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा भावनगर मण्डल पर विभिन्न निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिन पर लगभग 350 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे. इन कार्यों में लिमिटेड हाइट सबवे/रोड अंडर ब्रिज एवं अन्य संरचनात्मक विकास कार्य आदि शामिल है. इसके अतिरिक्त 40 नये ब्रीज बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिये गये हैं और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जायेगा.

बारिश **महाराष्ट्र, हिमाचल, दिल्ली व जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट, गोदावरी नदी उफान पर**

कई राज्यों में लाखों लोग प्रभावित, स्कूल बंद

नई दिल्ली/शिमला/जयपुर/मुंबई/चंडीगढ़, 4 सितंबर (वार्ता). उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मानसून इस बार कहर बनकर टूटा है. दिल्ली, हिमाचल, महाराष्ट्र और राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं.

नदी-नालों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और जनजीवन अस्त-व्यस्त है. स्कूल-कॉलेज बंद, सड़कें जलमग्न और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जारी है. देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर चुका है. यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली सड़क को बंद करना पड़ा है. हालांकि दिल्ली मेट्रो ने सेवा को चालू रखा है और इंटरचेंज सुविधा सामान्य रूप से जारी है. पंजाब की बात करें तो यहां 1655 गांवों में बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य सरकार ने सभी स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया है. पठानकोट, अमृतसर और गुरदासपुर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से तिब्बती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है. कुल्लू, मनाली और शिमला की बस्तियों में मठ, घर व शयनगृह जलमग्न हो गए हैं. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कुल्लू में आपात राहत के लिए 4 लाख रुपये की सहायता दी है. चंडीगढ़ में स्थित सुखना लेक का जलस्तर 1164 फीट पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से दो फीट ऊपर है. किशनगढ़-बापूधाम मार्ग को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.

बाढ़ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली. लगातार बारिश और बाढ़ से उत्पन्न संकटों को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी किया है. याचिका में मांग की गई है कि इन राज्यों में आपदा प्रबंधन की विफलता, जान-माल के नुकसान और विस्थापित नागरिकों के पुनर्वास को लेकर कोर्ट हस्तक्षेप करे.